माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. वी. गुप्ता के सामने,

छावनी बोर्ड, अम्बाला, अपीलकर्ता
बनाम
बरहमा नंद, प्रतिवादी।
1979 के आदेश क्रमांक 35 से द्वितीय अपील
21 जनवरी 1980

छावनी अधिनियम (1924 का द्वितीय) - धारा 273(3) - किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने वाला बोर्ड - असफल होने पर बर्खास्तगी का आदेश - अधिनियम के तहत अपील और संशोधन में पूरी तरह से चुनौती दी गई - फिर ऐसे आदेश की वैधता को चुनौती देने के लिए मुकदमा दायर किया गया - मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण - क्या अधिनियम के तहत अंतिम आदेश पारित होने पर उत्पन्न होता है।

अनहिनिर्धारित किया गया कि यदि छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 273(1) के तहत विचार किए गए कार्रवाई के कारण को बर्खास्तगी के मूल आदेश पर उत्पन्न माना जाता है, तो अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपील और पुनरीक्षण का वैधानिक उपाय भ्रामक हो जाता है। वास्तव में, बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करने वाला व्यक्ति अधिनियम के तहत अपील और पुनरीक्षण दायर करेगा, और इस प्रकार मूल आदेश अपील या पुनरीक्षण में पारित बाद के आदेशों में विलीन हो जाता है। इन परिस्थितियों में, कार्रवाई का कारण उस तारीख को उत्पन्न हुआ माना जाएगा जब अधिनियम के तहत अंतिम आदेश पारित किया जाता है, यानी अपील या पुनरीक्षण में। (पैरा 5)

श्री ए.एस. गर्ग, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अम्बाला के न्यायालय के आदेश, दिनांक 17 फरवरी, 1979 से दूसरी अपील, श्री यू.बी. खंडूजा, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, अम्बाला छावनी के दिनांक 27 जुलाई, 1978 के आदेश को पलटते हुए, स्वीकार करते हुए अपील और, गुण-दोष के आधार पर मुकदमे की सुनवाई के लिए मुकदमे को विद्वान ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया और पक्षों को 2 मार्च, 1979 को विद्वान ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया।

अपीलकर्ताओं के लिए वकील एम. आर. अग्निहोत्री और वी. के. वशिष्ठ।

प्रतिवादी की ओर से जे.एल. गुप्ता एवं जगदीश सिंह, अधिवक्ता।

निर्णय

माननिय न्यायमूर्ति श्री जे. वी. गुप्ता,

(1) प्रतिवादी-अपीलकर्ता ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के 17 फरवरी 1979 के आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है, जिसके तहत मुकदमे को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया है और गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दिया गया है।

(2) इस अपील में निर्णय लिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि छावनी अधिनियम, 1924 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 273(3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मुकदमा समय के भीतर है या नहीं। त्वरित संदर्भ के लिए, धारा 273 उप-धारा (3) देखी जा सकती है जो इस प्रकार है: -

> "कोई भी मुकदमा, जैसा कि उप-धारा (1) में वर्णित है, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह अचल संपत्ति की वसूली या उसके स्वामित्व की घोषणा के लिए एक कार्रवाई न हो, जब कार्य का कारण उत्पन्न होता है उस तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद शुरू नहीं किया जाएगा। "

(3) स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी-प्रतिवादी, जो छावनी बोर्ड, अंबाला का ड्राइवर था, और छावनी बोर्ड की स्वच्छता शाखा में कार्यरत था, को एक संकल्प द्वारा, दिनांक 21 मई, 1974 के आदेश द्वारा, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वादी ने छावनी अधिनियम में निर्धारित प्राधिकारियों के समक्ष अपील की, जिसे 21 सितंबर, 1974 को खारिज कर दिया गया, और फिर उसने विभाग में एक संशोधन को प्राथमिकता दी, जिसे 4 जून, 1975 को खारिज कर दिया गया, और निर्णय के बारे में उसे 10 जून, 1975 को सूचित किया गया। यह घोषित करने के लिए वर्तमान मुकदमा कि वादी को ड्राइवर के पद से हटाना, - इसके संकल्प संख्या 9, दिनांक 21 मई, 1974 के तहत, अवैध, गलत, अन्यायपूर्ण, शून्य और अप्रभावी था, 12 नवंबर, 1975 को दायर किया गया था। प्रतिवादी-अपीलकर्ता की ओर से दायर लिखित बयान में, एक दलील दी गई थी कि मुकदमा समय से बाधित है क्योंकि इसे बर्खास्तगी के मूल आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर, यानी 21 मई 1974, को दायर नहीं किया गया था। जैसा कि अधिनियम की धारा 273(3) के तहत विचार किया गया है। इस प्रकार निर्णय लिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि वर्तमान मामले में कार्रवाई का कारण कब उत्पन्न हुआ। ट्रायल कोर्ट ने यह विचार किया कि छह महीने की सीमा को मूल आदेश की तारीख, यानी 21 मई, 1974 से गिना जाना चाहिए, और इस प्रकार मुकदमे को कालबाधित माना गया और परिणामस्वरूप इसे खारिज कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा यह भी देखा गया कि किसी कर्मचारी को अपील या पुनरीक्षण दायर करने का अधिकार देने वाले नियमों में

मात्र एक प्रावधान को कर्मचारी के मुकदमा दायर करने के अधिकार पर रोक लगाने वाला नहीं माना जा सकता है। वादी-प्रतिवादी की ओर से दायर अपील में, निचली अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया है और यह विचार किया है कि वादी का मुकदमा सामान्य सीमा कानून के तहत परिसीमा के भीतर था और बर्खास्तगी की तारीख, यानी 21 मई, 1974 तारीख से तीन साल के भीतर है। नतीजतन, मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए भेज दिया गया। रिमांड के इस आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादी-अपीलकर्ता इस न्यायालय में दूसरी अपील में आया है।

(4) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से सीता राम गोयल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड, कानपुर[1] और कैंटोनमेंट बोर्ड, फिरोजपुर कैंट बनाम बजरंग सिंह[2] पर भरोसा जताया है। सीता राम के मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार किया था कि "यह सिद्धांत कि वरिष्ठ अदालतें अपने विवेक से विशेषाधिकार रिट जारी नहीं कर सकती हैं, जब तक कि आवेदक ने विशेष अधिनियम के तहत अपने सभी उपचारों का उपयोग नहीं कर लिया हो, किसी मुकदमे पर लागू नहीं होता है।" इसके पैरा 24 में यह देखा गया है कि "वर्तमान मामले में कार्रवाई का कारण अपीलकर्ता को उसी क्षण मिला, जब बोर्ड के संकल्प के बारे में उसे सूचित किया गया था और वह परिसीमा शुरू होने की तारीख थी। गलत तरीके से बर्खास्तगी के संबंध में बोर्ड के खिलाफ मुकदमा दायर करने का उपाय, यदि कोई हो, उस तारीख से उसके पास उपलब्ध था और धारा 326 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर उस उपाय को आगे बढ़ाने के लिए वह कार्य खुला था। ये टिप्पणियाँ अपीलकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क का समर्थन करती हैं कि कार्रवाई का कारण 21 मई, 1974 को अर्जित माना जाएगा, और चूंकि मुकदमा उसके छह महीने के भीतर स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए यह अधिनियम की धारा 273(3) के तहत कालातीत है। जहां तक कैंटोनमेंट बोर्ड, फिरोजपुर कैंट के मामले (सुप्रा) का सवाल है, इससे अपीलकर्ता को ज्यादा मदद नहीं मिली। इसके पैरा 7 में यह देखा गया है कि "इन परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि वर्तमान मामला पूरी तरह से छावनी अधिनियम की धारा 273 की उप-धारा (3) द्वारा शासित है और वर्तमान के एक मुकदमे के लिए निर्धारित सीमा की अवधि प्रकृति में कार्रवाई के कारण के संचय की तारीख से केवल छह महीने हैं, जिसे इस मामले में 29 सितंबर, 1955 को अर्जित माना जाना चाहिए जब बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था। भले ही टर्मिनस-ए-क्को को 3 जनवरी, 1957 को दूसरी अपील को खारिज करने की तारीख के रूप में लिया गया था, 2 दिसंबर, 1958 को दायर किया गया वर्तमान मुकदमा निराशाजनक रूप से समय से

[1] ए आई आर 1958 अस सी 1036

[2] 1961 पी अल आर 407

बाधित है। इन परिस्थितियों में, उस मामले में टर्मिनस-ए-क्को का प्रश्न अंतिम रूप से तय नहीं किया गया था क्योंकि मुकदमा पहले ही दूसरी अपील के खारिज होने की तारीख से ही कालातीत हो चुका था।

(5) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने गुजरात उच्च न्यायालय के मोती लाई संकलचंद जैन बनाम अहमदाबाद शहर[3] के नगर निगम के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1945 के तहत एक समान प्रश्न उत्पन्न हुआ था। सीता राम के मामले (सुप्रा) से निपटने के दौरान, यह देखा गया है कि "सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी ओर से दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद पार्टियों ने माना कि वादी को खारिज करने वाले बोर्ड के संकल्प को एक डिक्री के बराबर नहीं किया जा सकता है और इसलिए, यह आगे माना गया कि विलय का सिद्धांत जो डिक्री को नियंत्रित करता है वह बर्खास्तगी के आदेश और बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित अपील आदेश को नियंत्रित नहीं कर सकता है। मोतीलाल मामले (सुप्रा) में विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, "यदि विलय का सिद्धांत मामलों पर लागू नहीं किया जाता है तो या तो अपील का वैधानिक अधिकार भ्रामक होगा या मुकदमा दायर करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। उक्त धारा द्वारा इतने कठोर परिणाम पर विचार नहीं किया गया है। विलय के सिद्धांत को लागू करके भी ऐसे कठोर परिणाम से बचा जा सकता है। विलय के सिद्धांत को लागू करने से अधिक सामंजस्य स्थापित होता है और पीड़ित कर्मचारी के सभी अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है। जिस हद तक यह पीड़ित कर्मचारी के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है, इसकी प्रयोज्यता कानून के शासन के लिए अनुकूल है। यह निष्कर्ष सोमनाथ साहू बनाम उड़ीसा राज्य[4] के रूप में रिपोर्ट किए गए बाद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहुंचा गया है, जिसमें यह माना गया है कि विलय का सिद्धांत प्रशासनिक आदेशों पर भी समान रूप से लागू होता है। इस प्रकार, मैं विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियों से सम्मानजनक सहमत हूं। यदि अधिनियम की धारा 273(3) के तहत विचार किए गए कार्रवाई का कारण बर्खास्तगी के मूल आदेश, यानी 21 मई, 1974 को उत्पन्न हुआ माना जाता है, तो अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपील और पुनरीक्षण का वैधानिक उपाय भ्रामक हो जाता है। वास्तव में, बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करने वाला व्यक्ति अधिनियम के तहत अपील और पुनरीक्षण दायर करेगा और इस प्रकार मूल आदेश अपील या पुनरीक्षण में पारित बाद के आदेशों में विलीन हो जाता है। इन परिस्थितियों में, कार्रवाई का कारण उस तारीख को उत्पन्न हुआ माना जाएगा जब अधिनियम के तहत अंतिम आदेश पारित किया गया था, यानी या तो अपील में या पुनरीक्षण में। मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, वादी-प्रतिवादी

[3] 1973 अम सी सी 151

[4] 1965 यू जे (अस सी) 351.

द्वारा 12 नवंबर, 1975 को दायर किया गया मुकदमा, पुनरीक्षण में पारित आदेश, दिनांक 4 जून, 1975 से छह महीने के भीतर है। मामले के इस दृष्टिकोण में, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या बर्खास्तगी के आदेश को अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा एक आदेश कहा जा सकता है या नहीं, इस अपील में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

(6) ऊपर दर्ज कारणों से, यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा